

## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की राजस्थान में संचालित प्रमुख परियोजनाएँ
2.	देश के पहले हार्ड रॉक ब्लॉक भाटीखेड़ा की नीलामी
3.	केन्द्रीय बजट - 2026-27 से राजस्थान को होने वाले संभावित लाभ
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के स्टेट ब्राण्ड एम्बेसेडर : के. के. गुप्ता 2. सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला : राजस्थान पहली बार शामिल 3. नमिता गोखले - भारतेन्दु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 4. पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमसिंह भड़ाना का निधन 5. डॉ. मुकेश पंचोली - NEXTGEN ICON AWARD 2026 6. कोग्निवेरा पोलो कप-2026 7. 5वीं सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप : जयपुर 8. GMDC और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीच MoU 9. प्रदेश का पहला ई-सेवा केन्द्र : पाली
5.	ऑरेंज इकोनॉमी: संघीय बजट वर्ष 2026-27
6.	16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट
7.	वस्त्र क्षेत्रक: केन्द्रीय बजट वर्ष 2026-27
8.	भारत विस्तार - Bharat - VISTAAR
9.	डोनेट्स्क
10.	राफा क्रॉसिंग
11.	'बायोफार्मा शक्ति' (Biopharma SHAKTI) पहल: केन्द्रीय बजट वर्ष 2026-27



## राजस्थान परिदृश्य

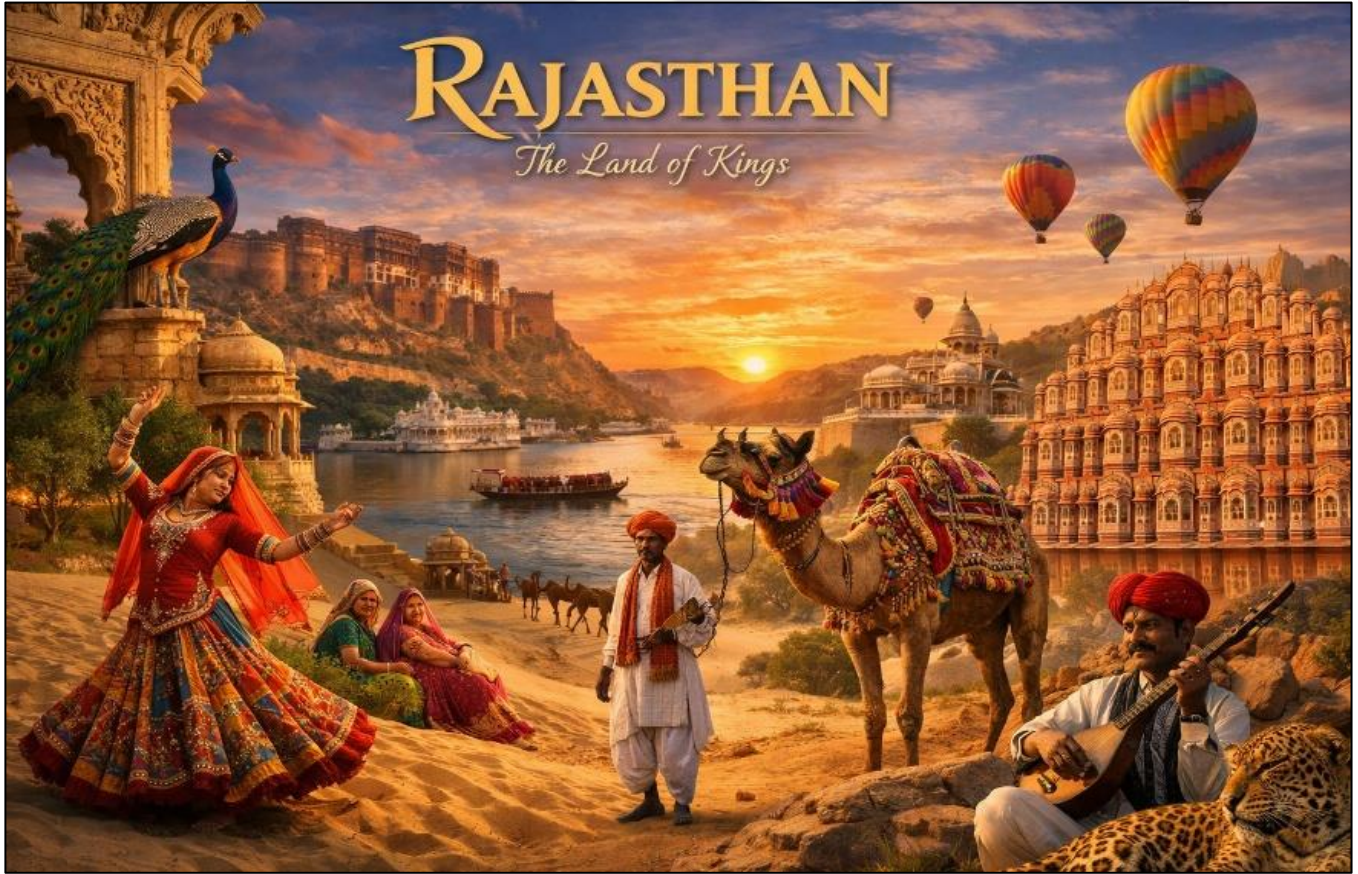


### केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की राजस्थान में संचालित प्रमुख परियोजनाएँ



**चर्चा में क्यों?**

- हाल ही में, केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में संचालित प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी प्रदान की।



**मुख्य बिन्दु:**

- केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नवीनीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के अनुसार टिकाऊ एवं जिम्मेदार पर्यटन गंतव्यों का विकास करना है।

--:2:--

# Daily Current Affairs

Date : 03 February, 2026



राजस्थान में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण:

क्रमांक	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)
1.	<b>स्वदेश दर्शन 1.0</b>	283.47 करोड़
i.	जयपुर जिले में सांभर झील टाउन तथा अन्य स्थलों का विकास (सितंबर, 2015)	50.01 करोड़
ii.	गोविंद देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी मंदिर (सीकर) तथा नाथद्वारा मंदिर (राजसमंद) का एकीकृत विकास (सितंबर, 2016)	75.80 करोड़
iii.	<b>आध्यात्मिक सर्किट का विकास : चूरू (सालासर बालाजी) - जयपुर (श्री सामोद के बालाजी, घाट के बालाजी, बंधे के बालाजी) - विराटनगर (बीजक, जैन नसियाँ, अंबिका मंदिर) - भरतपुर (कामाँ क्षेत्र) - धौलपुर (मचकुंड) - दौसा (मेहंदीपुर बालाजी) - चित्तौड़गढ़ (सांवलियाजी मंदिर) का विकास (मार्च, 2017)</b>	87.05 करोड़
iv.	<b>धरोहर सर्किट का विकास : राजसमंद (कुंभलगढ़ किला) - जयपुर (जयपुर में फैसेड इल्यूमिनेशन तथा नाहरगढ़ किला) - झालावाड़ (गागरोन किला) - चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ़ किला) - जैसलमेर (जैसलमेर किला) - हनुमानगढ़ (गोगामेड़ी) - उदयपुर (प्रताप गौरव केंद्र) - धौलपुर (बाग-ए-नीलोफर तथा पुरानी छावनी) - नागौर (मीरा बाई स्मारक, मेड़ता) - टोंक (सुनहरी कोठी) का विकास (जून, 2017)</b>	70.61 करोड़

--3--



उत्कर्ष® Jodhpur : JALORI GATE CIRCLE, JODHPUR | Support@utkarsh.com | Call us at : 9829 213 213  
Jaipur : NEAR MAHESH NAGAR THANA, GOPALPURA BYPASS ROAD, JAIPUR

# Daily Current Affairs

Date : 03 February, 2026



2.	<b>स्वदेश दर्शन 2.0</b>	180.83 करोड़
i.	केशवरायपाटन मन्दिर (बूँदी) का विकास (फरवरी, 2024, जून, 2025 में संशोधित)	21.65 करोड़
ii.	श्री खाटूश्याम जी मंदिर (सीकर) का विकास कार्य (मार्च, 2025)	87.87 करोड़
iii.	श्री करणी माता मंदिर (बीकानेर) का विकास कार्य (जुलाई, 2025)	22.58 करोड़
iv.	मालासेरी डूंगरी, (भीलवाड़ा) का विकास (जुलाई, 2025)	48.73 करोड़
3.	<b>प्रसाद (PRASHAD) योजना - पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल, हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव</b>	32.64 करोड़
i.	पुष्कर का एकीकृत विकास (सितंबर, 2019 में संशोधित)	32.64 करोड़
4.	<b>राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता (SASCI)</b>	145.92 करोड़
i.	आमेर - नाहरगढ़ तथा आसपास के क्षेत्र का विकास (नवंबर, 2024)	49.31 करोड़
ii.	जल महल (जयपुर) का विकास (नवंबर, 2024)	96.61 करोड़
5.	<b>केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (ACA)</b>	42.33 करोड़
i.	जैसलमेर सेक्टर में श्री तनोट परिसर में सीमा पर्यटन का विकास	17.68 करोड़
ii.	बूँदी में नवल सागर झील पर म्यूज़िकल फॉउंटैन तथा जल-परदा आधारित मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन शो की स्थापना	9.26 करोड़
iii.	अजमेर रेलवे स्टेशन	5.52 करोड़
iv.	जयपुर रेलवे स्टेशन	4.88 करोड़
v.	चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन	4.99 करोड़

**केंद्रीय सहायता का कुल योग (Total Central Assistance) - ₹685.19 करोड़**

--:4:--

## देश के पहले हार्ड रॉक ब्लॉक भाटीखेड़ा की नीलामी

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, केन्द्रीय खान मंत्रालय ने भारत के पहले हार्ड रॉक ब्लॉक भाटीखेड़ा की नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न की।



### मुख्य बिन्दु:

- रेयर अर्थ एलीमेंट्स (REE) के समृद्ध भंडारों के लिए प्रसिद्ध भाटीखेड़ा बालोतरा ज़िले के सिवाना में स्थित है तथा भारत का पहला हार्ड रॉक ब्लॉक भी है।
- जातव्य है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग व एटोमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट की ओर से रिसर्च के पश्चात् सिवाना के भाटीखेड़ा में 1.34 वर्ग किमी के ब्लॉक को ऑक्शन के लिए चिह्नित किया गया था।
- इस क्षेत्र में पाए जाने वाले माइक्रो ग्रेनाइट में रेयर अर्थ मिनरल्स (दुर्लभ मृदा तत्त्व) की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है।

--:5:--

# Daily Current Affairs

Date : 03 February, 2026



- खान मंत्रालय के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट (AMD) ने इन क्षेत्रों में अब तक कुल 47 विस्तृत भूगर्भीय सर्वेक्षण किए हैं।
- इन सर्वेक्षणों में विशेष रूप से बालोतरा की सिवाना तहसील को रेयर अर्थ एलिमेंट्स के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

## प्रमाणित भंडार:

- सिवाना (बालोतरा) में मौजूद दुर्लभ व सामरिक खनिजों में थोरियम (81.8 मिलियन टन), नियोडिमियम (67.6 मिलियन टन), टैंटलम (6.8 मिलियन टन) और जिरकोनियम (52.5 मिलियन टन) शामिल हैं।
- इसके अलावा इस क्षेत्र में नाइओबियम, रेनियम, रेडियम और रुबिडियम जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज भी पाए गए हैं।

## सामरिक महत्त्व:

- ये खनिज परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, हाई-टेक मैनुफैक्चरिंग तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **नोट** : वर्तमान में चीन दुनिया के 60 प्रतिशत से अधिक रेयर अर्थ खनन और 90 प्रतिशत से अधिक प्रोसेसिंग (रिफाइनिंग) करता है।
- **आयात पर निर्भरता** : भारत अपनी रेयर अर्थ मैग्नेट और संबंधित कच्चे माल की माँग का 80-90 प्रतिशत हिस्सा चीन से आयात करता है।

## फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **रेयर अर्थ कॉरिडोर** : केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 'डेडीकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर' बनाने की घोषणा की गई है ताकि खनन और प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा सके।
- **नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन** : जनवरी, 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात वर्षों के लिए ₹34,300 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 'नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन' (NCMM) को स्वीकृति प्रदान की। इस मिशन का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है।

--6--

## केन्द्रीय बजट - 2026-27 से राजस्थान को होने वाले संभावित लाभ



### चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2026 को संसद में केन्द्रीय बजट - 2026-27 पेश किया।



### मुख्य बिन्दु:

- नोट :** निर्मला सीतारमण द्वारा केन्द्रीय वित्त मंत्री के रूप में लगातार नौवां बजट प्रस्तुत किया गया। साथ ही, भारतीय इतिहास में पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया गया।  
**राजस्थान को होने वाले संभावित लाभ:**
- बजट में देश भर के 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर को मजबूत करने हेतु प्रावधान किए गए हैं, जिससे राजस्थान को भी लाभ होगा। लिक्विडिटी सपोर्ट, क्रेडिट गारंटी और ट्रांजेक्शन सेटलमेंट प्रोग्राम से जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों में लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
- चैलेन्ज मोड पर मेगा टैक्सटाइल पार्क स्थापित करने से टैक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम से भीलवाड़ा, बालोतरा, जयपुर और जोधपुर के कपड़ा उद्योग को लाभ होगा।

- देश में 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और रियल स्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) से मिलने वाले वित्त से राज्य के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर आदि शहर लाभान्वित होंगे।
- **म्युनिसिपल बॉन्ड को प्रोत्साहन** : बड़े शहरों द्वारा 1000 करोड़ रुपये से अधिक के एकल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है, जो शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में मदद करेगा।
- बजट-2026-27 में सोलर ग्लास मैनुफेक्चरिंग में प्रयोग आने वाले सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इस घोषणा से राजस्थान जो सौर ऊर्जा में अग्रणी प्रदेश है, के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में सौर ऊर्जा से नई निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी।
- बजट 2026-27 में लखपति दीदी योजना की सफलता को विस्तार देते हुए 'शी-मार्ट' (SHE-Marts) की स्थापना का प्रावधान किया गया। जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा बनाए गए उत्पादों को सीधा बाजार उपलब्ध कराना और बिचौलियों को खत्म करना है। इस घोषणा से राजस्थान में श्रम बल में महिलाओं के योगदान को विस्तार मिलेगा।
- देश के प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने का अभियान शिक्षा को सुलभ बनाएगा। इस तरह राजस्थान के सभी 41 जिलों में छात्राओं के लिए छात्रावास खुलेंगे।
- राज्य सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति, AI-ML नीति और डेटा सेंटर नीति लागू की हैं। बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, एआई मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट मेनुफेक्चरिंग स्कीम, डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को दिए गए इंसेंटिव्स का फायदा लेते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर का हब बनेगा।
- केंद्रीय बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए 'SME विकास निधि' और 'आत्मनिर्भर भारत टॉपअप' की घोषणा की गई है। इन घोषणाओं से राजस्थान के छोटे उद्योगों के ग्लोबल बिजनेस हाउस बनने की राह प्रशस्त होगी।
- वर्ष 2026-27 के बजट में पहली बार ₹10228 करोड़ से अधिक की राशि राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए आवंटित की गई है। यह राशि वर्ष 2009-14 के बजट की तुलना में लगभग 15 गुना अधिक है।

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के स्टेट ब्राण्ड एम्बेसेडर : के. के. गुप्ता</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के राज्य समन्वयक और डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के. के. गुप्ता को स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का स्टेट ब्राण्ड एम्बेसेडर नियुक्त किया गया।</li><li>के. के. गुप्ता डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्हें 'डूंगरपुर मॉडल' के लिए जाना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप डूंगरपुर राजस्थान का पहला खुले में शौच मुक्त (ODF) शहर बना था।</li><li>उल्लेखनीय है कि के. के. गुप्ता पूर्व में भी दो बार राज्य के स्वच्छता ब्राण्ड एम्बेसेडर रह चुके हैं।</li></ul>
2.	<p><b>सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला : राजस्थान पहली बार शामिल</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हो रहे सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला - 2026 (39वाँ संस्करण) में राजस्थान पहली बार भाग ले रहा है।</li><li>इस मेले में राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसिको) द्वारा 'राजस्थान चौक' बनाया गया है। यहाँ राजस्थान की कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है।</li><li>इस मेले में राजस्थान के हस्तशिल्प और ODOP (ONE DISTRICT ONE PRODUCT) उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए 20 स्टॉल्स लगाई गई हैं।</li></ul>
3.	<p><b>नमिता गोखले - भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>प्रख्यात लेखिका और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह-संस्थापक नमिता गोखले को हाल ही में 'भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया।</li><li>उन्हें यह पुरस्कार बनारस लिटरेचर फेस्टिवल (BLF) 2026 के दूसरे संस्करण के दौरान प्रदान किया गया।</li><li>नमिता गोखले अपने पहले उपन्यास 'पारो: ड्रीम्स ऑफ पैशन' के लिए जानी जाती हैं, जिसे एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। उन्हें वर्ष 2021 में उनके उपन्यास 'थिंग्स टू लीव बिहाइंड' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है।</li></ul>

4.	<p><b>पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमसिंह भड़ाना का निधन</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमसिंह भड़ाना का निधन हो गया।</li><li>वे अलवर की थानागाजी विधानसभा सीट से दो बार (2008 और 2013) विधायक रहे।</li><li>वसुंधरा राजे सरकार (2013-2018) में उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया।</li></ul>
5.	<p><b>डॉ. मुकेश पंचोली - NEXTGEN ICON AWARD 2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, प्रख्यात शिक्षाविद् डॉ. मुकेश पंचोली को प्रतिष्ठित 'NEXTGEN ICON AWARD 2026' से सम्मानित किया गया।</li><li>यह पुरस्कार राजस्थान के सबसे बड़े कॉर्पोरेट और आइकॉनिक अवार्ड शो NextGen Icon Awards 2026 के दौरान दिया गया।</li><li>उन्हें शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, उत्कृष्ट योगदान और विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया।</li></ul>
6.	<p><b>कोग्निवेरा पोलो कप-2026</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, जयपुर में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप-2026 के फाइनल में टीम जयपुर ने वी पोलो (V Polo) को 5-2 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।</li><li>विजेता टीम जयपुर के लिए लांस वॉटसन ने 4 और पद्मनाभ सिंह ने एक गोल किया।</li><li>इस कप के लिए 7 फीट ऊँची ट्रॉफी अनावरित की गई, जो दुनिया की सबसे ऊँची पोलो ट्रॉफी है। वजन - 65 किलो। इसको बनाने में 10 लाख रुपए लागत आई जिसे जयपुर के रामशरण जांगिड़ ने तैयार किया।</li></ul>
7.	<p><b>5वीं सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप : जयपुर</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>आयोजन :</b> सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।</li><li><b>आयोजक :</b> एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया।</li><li><b>विजेता :</b> सीनियर मेंस वर्ग के फाइनल में राजस्थान ने महाराष्ट्र को 5-3 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता।</li><li>सीनियर विमेंस वर्ग में पुड्डुचेरी ने राजस्थान को 3-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता।</li></ul>

8.

## GMDC और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीच MoU

- गुजरात खनिज विकास निगम (GMDC) और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (MLSU), उदयपुर के भू-विज्ञान विभाग के बीच हाल ही में खनिज अन्वेषण और शैक्षणिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **उद्देश्य** : खनिज संसाधनों की खोज (Exploration) और अनुसंधान (Research) के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करना।
- समझौते के तहत अंबाजी क्षेत्र में खनिज खोज और माइनिंग के प्रयास शुरू किए जा चुके हैं।

9.

## प्रदेश का पहला ई-सेवा केन्द्र : पाली

- न्यायिक कार्यों के डिजिटलीकरण के तहत राजस्थान का पहला ई-सेवा केन्द्र (e-Service Center) पाली जिला न्यायालय परिसर में स्थापित किया जा रहा है।
- इस केंद्र के माध्यम से आम नागरिकों और अधिवक्ताओं को न्यायिक प्रक्रियाओं, केस स्टेटस और डिजिटल दस्तावेजों तक आसान पहुँच प्राप्त होगी। इन ई-सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी।

## जल विज्ञान मॉडलिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम : काजरी, जोधपुर

- केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) द्वारा 2 से 6 फरवरी, 2026 तक जल विज्ञान मॉडलिंग (Hydrological Modelling) पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- **विषय** : सॉइल एंड वॉटर असेसमेंट टूल (SWAT) का उपयोग करके जल विज्ञान मॉडलिंग का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण।

## आर्थिक घटनाक्रम

### ऑरेंज इकोनॉमी: संघीय बजट वर्ष 2026-27

#### चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने संघीय बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी (क्रिएटिव इकोनॉमी) पर ज़ोर दिया। साथ ही, रोजगार सृजित करने, नवाचार, निर्यात और सॉफ्ट पावर में इसकी भूमिका को रेखांकित किया।



#### मुख्य बिन्दु:

#### ऑरेंज इकोनॉमी क्या है?

- **प्रतिपादन:** 'ऑरेंज इकोनॉमी' शब्द का प्रतिपादन 2013 में कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान डुके मार्केज़ और फेलिप बुइट्रेगो ने अपनी पुस्तक "ऑरेंज इकोनॉमी: एन इनफिनिट ऑपच्युनिटी" में किया था।
- यह उन ज्ञान-आधारित आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है, जहां विचारों और रचनात्मकता को सांस्कृतिक वस्तुओं एवं सेवाओं में बदल दिया जाता है। इनका मूल्य मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा द्वारा निर्धारित होता है।

-:12:-

- पारंपरिक विनिर्माण आधारित संवृद्धि के विपरीत, इस अर्थव्यवस्था में शामिल क्षेत्रक भौतिक वस्तुओं की बजाय विचारों, कलात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक पूंजी से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं।
- **प्रमुख क्षेत्रक:** इसमें दृश्य-श्रव्य मीडिया (फिल्म, टीवी), लाइव संगीत कार्यक्रम, गेमिंग उद्योग, डिजाइन, थिएटर आदि शामिल हैं।

## बजट 2026-27 की मुख्य घोषणाएँ

- **AVGC (एनीमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स) क्षेत्रक:** 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने के लिए मुंबई स्थित भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT) को सहायता दी जाएगी।
- **डिजाइन शिक्षा को मजबूती:** 'चैलेंज प्रतिस्पर्धा' के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र में एक नया राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID) स्थापित किया जाएगा।
- वर्तमान में भारत में 7 NIDs हैं, जिन्हें राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है।

## अन्य रंगों में वर्गीकृत अर्थव्यवस्थाएँ

- **ग्रीन इकोनॉमी:** संधारणीय, कम कार्बन उत्सर्जक और ऊर्जा-दक्ष उद्योग
  - **व्हाइट इकोनॉमी:** स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल क्षेत्रक
  - **ब्लू इकोनॉमी:** समुद्री और महासागर- आधारित गतिविधियां
  - **सिल्वर इकोनॉमी:** वृद्ध होती आबादी और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी सेवाएं
- ## ऑरेंज इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति
- विश्व भर में, क्रिएटिव इकोनॉमी से वार्षिक रूप से \$2 ट्रिलियन से अधिक का राजस्व और लगभग 50 मिलियन नौकरियां सृजित होने का अनुमान है।
  - UNCTAD के अनुमानों के अनुसार, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ देशों की GDP में 0.5% से लेकर 7% से अधिक का योगदान देते हैं।
  - भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री का आकार \$30 बिलियन का है और इसमें रोजगार का हिस्सा भारत की कामकाजी आबादी का लगभग 8% है।

## 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

### चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत की। 16वें वित्त आयोग का गठन 2023 में किया गया था। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं।



### मुख्य बिन्दु:

- आयोग की मुख्य सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ये सिफारिशें वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू होंगी।

--:14:--

## वित्त आयोग द्वारा राज्यों के बीच हस्तांतरण-मानदंड

मानदंड	15वें वित्त आयोग (2021-26)	16वें वित्त आयोग (2026-31)
आय अंतर	45%	42.5%
जनसंख्या (2011)	15%	17.5%
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (नियंत्रण के प्रयास)	12.5%	10%
क्षेत्रफल	15%	10%
वन आवरण	10%	10%
कर एवं राजकोषीय सुधार	2.5%	-
GDP में योगदान	-	10%
कुल	100%	100%

### वित्त आयोग

- वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद-280) है।
- **गठन:** इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल में या जरूरत पड़ने पर पहले किया जाता है।
- **संरचना:** अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए की जाती है।
- **अनुच्छेद 281** के अनुसार केंद्र सरकार वित्त आयोग की रिपोर्ट और उस पर कार्यवाही का ज्ञापन संसद के पटल पर रखती है।

## 16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें

- **ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical devolution):** विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% ही रहेगी। यह प्रतिशत 15वें वित्त आयोग जैसा ही है।
  - विभाज्य पूल में शामिल होता है सकल कर राजस्व। हालांकि, इसमें से कर संग्रह की लागत, उपकर (सेस) और अधिभार (सरचार्ज) शामिल नहीं होते।
  - **क्षैतिज हस्तांतरण:** यह 41% हिस्सेदारी को राज्यों में बांटने की पद्धति है।
  - इस बार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में राज्यों के योगदान को एक नया मानदंड बनाया गया है।
  - राज्यों के बीच आय में अंतर और राज्य के क्षेत्रफल को कम महत्त्व दिया गया है।
  - इस बदलाव के फलस्वरूप दक्षिणी राज्यों को अधिक हिस्सा मिलने की संभावना है।
- समष्टि (मैक्रो) आर्थिक स्थिति और राजकोषीय स्थिरता:**
- राज्यों को राजकोषीय घाटा अपने राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का अधिकतम 3% तक सीमित रखना चाहिए।
  - हालांकि पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत मिले ऋण को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

## HOW STATES SHARE THE MONEY BAG

Total divisible pool of central taxes is up 86%, from ₹56 lakh crore under the 15th Finance Commission to ₹104 lakh crore under the 16th. While all states will get more funds in absolute terms, their shares have shifted—mostly marginally. On this front, only one of the five southern states stands to lose

State	15th FC	16th FC	Change in share (% point)	State	15th FC	16th FC	Change in share (% point)
UP	17.93	17.62	-0.31	Kerala	1.94	2.38	0.44
Bihar	10.06	9.95	-0.11	Telangana	2.13	2.17	0.04
<b>MP</b>	<b>7.89</b>	<b>7.35</b>	<b>-0.54</b>	Punjab	1.79	2.00	0.21
West Bengal	7.52	7.22	-0.31	Haryana	1.08	1.36	0.28
Maharashtra	6.13	6.44	0.31	Arunachal	1.76	1.35	-0.41
Rajasthan	5.98	5.93	-0.05	Uttarakhand	1.1	1.14	0.04
Odisha	4.63	4.42	-0.21	Himachal	0.8	0.91	0.11
Andhra	4.11	4.22	0.11	Tripura	0.7	0.64	-0.06
<b>Karnataka</b>	<b>3.64</b>	<b>4.13</b>	<b>0.49</b>	Meghalaya	0.77	0.63	-0.14
Tamil Nadu	4.19	4.10	-0.09	Manipur	0.72	0.63	-0.09
Gujarat	3.4	3.76	0.36	Mizoram	0.5	0.56	0.06
Jharkhand	3.31	3.36	0.05	Nagaland	0.57	0.48	-0.09
Chhattisgarh	3.41	3.30	-0.11	Goa	0.39	0.37	-0.03
Assam	3.13	3.26	0.13	Sikkim	0.39	0.34	-0.06

Note: FC is short for Finance Commission; figures for 15th & 16th FC are in %

## वस्त्र क्षेत्रक: केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27

### चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27 में वस्त्र क्षेत्रक के लिए एकीकृत कार्यक्रम घोषित किया गया।



### मुख्य बिन्दु:

- उद्देश्य:** फाइबर (रेशे) से लेकर फैशन तक और ग्रामीण उद्योगों से लेकर वैश्विक बाजारों तक संपूर्ण वस्त्र क्षेत्रक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

### एकीकृत कार्यक्रम के पांच उप-घटक

- राष्ट्रीय फाइबर (रेशा) योजना:** इसका लक्ष्य फाइबर क्षेत्रक में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
- यह योजना रेशम, ऊन व जूट जैसे प्राकृतिक रेशों के साथ-साथ मानव निर्मित और आधुनिक युग के नए रेशों को भी सहायता प्रदान करेगी।

- **वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना:** इस घटक का उद्देश्य मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत सहायता के माध्यम से पारंपरिक वस्त्र उद्योग संकुलों का आधुनिकीकरण करना है।
- **राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम:** हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए मौजूदा योजनाओं को इस एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत समाहित व मजबूत किया जाएगा।
- **टेक्स-इको पहल:** इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण के अनुकूल वस्त्र एवं परिधान निर्माण को बढ़ावा देना है।
- **समर्थ 2.0:** इसका लक्ष्य उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहन सहयोग के माध्यम से वस्त्र कौशल तंत्र का आधुनिकीकरण करना है।

## वस्त्र क्षेत्रक के लिए घोषित अन्य पहलें

- **महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल:** यह पहल खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती प्रदान करेगी। यह वैश्विक बाजार संपर्क और ब्रांडिंग आदि पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
- साथ ही, यह 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) पहल को भी समर्थन करेगी।
- **मेगा टेक्सटाइल पार्क्स और तकनीकी वस्त्र:** यह पहल तकनीकी वस्त्र क्षेत्रक में विकास को बढ़ावा देगी। यह औद्योगिक, चिकित्सा, रक्षा एवं अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए एक उच्च-क्षमता वाला क्षेत्रक है।

## भारत विस्तार - Bharat - VISTAAR

### चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय बजट वर्ष 2026-27 में कृषि विकास के लिए भारत-विस्तार शुरुआत करने का प्रस्ताव किया गया।



### मुख्य बिन्दु:

- भारत विस्तार (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस) एक बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल होगा।
- यह एग्रीस्टेक पोर्टल और कृषि पद्धतियों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्-ICAR के पैकेज को AI प्रणाली के साथ एकीकृत करेगा।
- एग्रीस्टेक को कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर-2.0 पर आधारित है।

--:20:--

# Daily Current Affairs

Date : 03 February, 2026



- यह विकेन्द्रीकृत भण्डार के रूप में कार्य करेगा, जो विभिन्न निजी व सार्वजनिक प्लेटफार्म पर कृषि संबंधी कंटेंट, सर्वोत्तम प्रथाओं व कृषि कौशल की खोज व उपलब्धता को आसान बनाएगा।

## महत्त्व:

- डेटा संचालित हस्तक्षेप - कृषि उत्पादकता में वृद्धि।
- किसानों द्वारा निर्णय लेने की क्षमता में सुधार।
- बाजार के जोखिमों को कम करना।
- वास्तविक समय निगरानी, कृषि विस्तार एवं परामर्श सेवाओं में सुधार।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

--:21:--



## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



### डोनेट्स्क



#### चर्चा में क्यों?

- रूस-यूक्रेन शांति वार्ता के वर्तमान चरण में डोनेट्स्क क्षेत्र का मुद्दा सबसे जटिल बनकर उभरा है।



#### मुख्य बिन्दु:

डोनेट्स्क क्षेत्र - अतिरिक्त जानकारी-

- अवस्थिति: पूर्वी यूक्रेन
- सीमाएँ: दक्षिण में ओजोन सागर।
- यह पूर्व में रूस से सीमा साझा करता है।
- संसाधन: कोयला, शेल गैस, नमक भण्डार (युजिन्स्का गैस क्षेत्र)



## राफा क्रॉसिंग



### चर्चा में क्यों?

- इजराइल द्वारा गाजा की राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को आंशिक रूप से फिर से खोल दिया गया है।



### मुख्य बिन्दु:

- **भौगोलिक अवस्थिति:** मिस्त्र व गाजा पट्टी के बीच स्थित। यह मिस्त्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा से सटा हुआ है।
- राफा क्रॉसिंग इजराइल से होकर नहीं गुजरता इसलिए इसे गाजा की जीवन रेखा कहा जाता है।
- गाजा पट्टी में प्रवेश और निकास के केवल दो अन्य क्रॉसिंग पॉइन्ट है और दोनों इजराइल के नियंत्रण में है।
  1. इरेज - Erez - उत्तरी गाजा में स्थित।
  2. केरेम शालोम - दक्षिणी गाजा में अवस्थित।



## ⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 📌

### 'बायोफार्मा शक्ति' (Biopharma SHAKTI) पहल: केंद्रीय बजट वर्ष 2026-27

#### 📢 चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उन्नति के लिए रणनीति) की घोषणा की। यह पहल भारत को वैश्विक जैव-विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है।



#### 📌 मुख्य बिन्दु:

#### बायोफार्मा शक्ति/ Biopharma SHAKTI

- **उद्देश्य:** भारत को बायोफार्मास्यूटिकल विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना। इसका मुख्य ध्यान बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करने पर है।

--:24:--

- **बायोलॉजिक्स:** ये वे दवाएं हैं, जो प्राकृतिक और जीवित स्रोतों जैसे पशु, पादप कोशिकाओं और सूक्ष्मजीवों से बनाई जाती हैं। इनमें टीके, रक्त व रक्त के घटक, सोमेटिक सेल्स, जीन थेरेपी, प्रोटीन आदि शामिल हैं।
- **बायोसिमिलर्स:** ये दवाएं बायोलॉजिक्स की ही नकल होती हैं। ये मूल जैविक उत्पाद के समान ही प्रभावशाली होती हैं और इनमें कोई महत्वपूर्ण चिकित्सकीय अंतर नहीं होता है।
- **वित्त-पोषण:** अगले 5 वर्षों के लिए ₹10,000 करोड़ का प्रावधान।

## रणनीति:

- 3 नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPER) स्थापित किए जाएंगे तथा 7 मौजूदा संस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा।
- पूरे देश में 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त नैदानिक (क्लिनिकल) परीक्षण केंद्रों का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों और एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा कैडर की नियुक्ति की जाएगी, ताकि दवाओं की मंजूरी में लगने वाला समय कम हो सके।

## भारत की जैव-अर्थव्यवस्था

- जैव-अर्थव्यवस्था का अर्थ एक ऐसी आर्थिक प्रणाली से है, जो भोजन, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए पादप, जानवरों एवं सूक्ष्मजीवों जैसे नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करती है।
- यह देश की GDP में 4.25% का योगदान देती है।
- भारत की जैव-अर्थव्यवस्था चार मुख्य उप-क्षेत्रों से संचालित होती है: जैव-औद्योगिक (47%), बायोफार्मा (35%), बायोएग्री (8%) और जैव-अनुसंधान (9%)।